

छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग
मंत्रालय, डी.के.एस. भवन,
रायपूर
आधिसूचना



कमांक 670 / श्रम / 2002

दिनांक 14-03-2002

चूँकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 (1) में बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बलात् श्रम प्रतिषेध किया गया है और आगे प्रावधान है कि इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा और,

चूँकि संसद द्वारा बंधक श्रम प्रथा (समाप्ति) अधिनियम 1976 (अधि. कमांक 1976 का 19) पारित किया जाकर बंधक श्रम प्रथा को समाप्त किये जाने का प्रावधान किया गया है । जिससे कि कमजोर वर्ग के व्यक्ति को आर्थिक एवं शारीरिक शोषण से बचाया जा सके, और

चूँकि बंधक श्रमिकों की पहचान के लिए पूर्व मध्यप्रदेश के छत्तीसगढ़ राज्य के सम्पूर्ण भाग में 1976 एवं इसके पश्चात् सर्वेक्षण कराये गये थे , और

चूँकि सर्वेक्षण में बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ के बंधक श्रमिक अन्य प्रदेशों में चिन्हांकित हुये थे जिन बंधक से मुक्त कराया जाकर छत्तीसगढ़ के कई जिलों में पुनर्वासित किया गया, और

चूँकि छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न भागों अंगी गी ऋण के कारण प्रथा के रूप में ऋणी अथवा उसका आश्रित ऋण देने वाले के यहाँ बगैर प्राप्ता वेतन के या ऋण को चुकाने के स्वज में बंधक के रूप में कार्य करता है या राज्य में अन्य किसी रूप में बंधक प्रथा विद्यमान है, और

चूँकि यह प्रथा मानव अधिकारों का हनन करती है और मानव श्रम के महत्व को निम्न स्तरीय बनाती है, और

चूँकि नये छत्तीसगढ़ राज्य के जनता के हितों की दृष्टि से संवैधानिक एवं वैधानिक दायित्वों के निर्वहण को गति दिया जाना आवश्यक है और इसके लिए बंधक श्रमिक की स्थिति को पुनर्विचार के दिग्दर्शक सुविधाजनक उपाय रखा जाना आवश्यक है और बंधक श्रम (समाप्ति) अधिनियम 1976 के प्रावधानों का प्रवर्तन अधिक सतर्कता से किया जाना जिससे कि यह कृपया राज्य में नहीं पाई जाये तथा राज्य की जनता की अपेक्षाओं की पूर्ति हो सके।

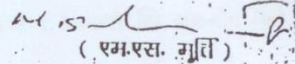
अतः अब बंधक श्रम प्रथा (समाप्ति) अधिनियम 1976 की धारा 10 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल जिला मजिस्ट्रेट को निम्न कर्तव्य एवं अधिकार अधिनियम की धारा 11 एवं 12 में निर्धारित कर्तव्यों के साथ अधिनियम एवं उसके अंतर्गत बने नियमों के प्रावधानों के प्रवर्तन हेतु दिये जाने का आदेश देते हैं ।

1. छत्तीसगढ़ राज्य में किसी भी रूप में चल रहे बंधक श्रम प्रथा को रोकने के लिए जिला मजिस्ट्रेट बंधक श्रमिकों की पहचान के लिए निर्धारित समयावधि के सर्वेक्षण की व्यवस्था करेंगे तथा इस पहचान के कार्य के लिए किसी एजेंसी की जिसे वे उपयुक्त समझे सहायता ले सकेंगे ।
2. जिला मजिस्ट्रेट को मुक्त कराये गये श्रमिकों को मुक्ति प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार होगा जिससे कि मुक्त बंधक श्रमिकों को राज्य एवं केन्द्र सरकार की गरीबों एवं सुविधाहीन जनता के लिए चलाई जा रही योजनाओं के अंतर्गत उपयुक्त रूप से पुनर्वासित किया जा सके ।
3. जिला मजिस्ट्रेट द्वारा राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गई राशि के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी किया जा सकेगा जिससे कि आसन बंद पुनर्वास के लिए चलाई जा रही योजनाओं में राशि के विमुक्त नहीं होने के कारण या संबंधित आसन को उपयोगिता का प्रमाण पत्र समय पर नहीं भेजे जाने के कारण पुनर्वास योजना प्रभावित न हो ।
4. जिला मजिस्ट्रेट बंधक श्रमिकों के पहचान के कार्य में लागे श्रेणीय कर्मचारियों, प्रवर्तन मशीनर सतर्कता समिति के सदस्यों एवं ऐसे आसकीय संस्था जो बंधक श्रमिकों के लिए समर्पित हो एवं अन्य संबंधित विभागों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था करें ।

जिला मजिस्ट्रेट उनकी जानकारी में आपे प्रत्येक संदेहात्मक बंधक श्रमिक के लिए प्रत्येक की संरचना होगी तथा उन्हें प्राप्त प्रत्येक जानकारी की सत्यता की जांच करायेगी ताकि अपराध करने वाला व्यक्ति अभिलेख में आ सके और पुनर्वास कार्यवाही की जा सके ।

6. जिला मजिस्ट्रेट को मुक्त हुए बंधक श्रमिक से उसके पूर्व मालिक द्वारा धरण के रजि में प्राप्त की गई राशि को मू- राजस्व के बकाया के समान राशि मानकर चरुड़ी के अधिकार होंगे तथा इस राशि को मुक्त हुए बंधक श्रमिक को मुआवजा किया जा सकेगा ।

राज्यपाल के नाम से एवं आदेशानुसार

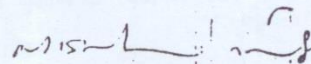

(एम.एस. गुप्ता)
सचिव
श्रम रवेला एवं युवक कल्याण

क्रमांक - 671 / श्रम / 2002

दिनांक 14-03-2002

प्रतिनिधि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1- समस्त सांगीय आयुक्त, छत्तीसगढ़
- 2- समस्त जिला मजिस्ट्रेट, छत्तीसगढ़
- 3- श्रम आयुक्त छत्तीसगढ़, रायपुर
- 4- संचालक, आसकीय प्रेस, राजनांदीगाँव की ओर अधिसूचना को असाधारण राजपत्र में प्रकाशन हेतु एवं राजपत्र की 50 प्रतियाँ भेजने हेतु प्रेषित ।


(एम.एस. गुप्ता)
सचिव
श्रम रवेला एवं युवक कल्याण